

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)

ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की चुनौतियाँ

डॉ. हंसराज

प्रवक्ता - वाणिज्य (संविदा)

विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैराना (शामली) उ.प्र. 247774

सार (Abstract)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets–NPAs) एक दीर्घकालिक संरचनात्मक चुनौती रही हैं, जिसने वित्तीय स्थिरता, बैंकिंग दक्षता और आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के पश्चात बैंकिंग क्षेत्र में तीव्र विस्तार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि, इस विस्तार ने परिसंपत्ति गुणवत्ता से संबंधित जोखिमों को भी जन्म दिया।

यह शोध-पत्र 1995 से 2010 तक की अवधि में भारतीय बैंकों में NPAs की प्रवृत्तियों, उनके निर्धारक कारकों (determinants), प्रभावों तथा नियंत्रण उपायों का विश्लेषण करता है। अध्ययन द्वितीयक डेटा पर आधारित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षणों तथा विभिन्न अकादमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि NPAs में प्रारंभिक उच्च स्तर के बाद गिरावट मुख्यतः नियामक सुधारों, SARFAESI अधिनियम, और बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों के कारण हुई। तथापि, यह गिरावट आंशिक रूप से ऋण पुनर्गठन और वर्गीकरण नीतियों के कारण भी थी। शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि NPAs केवल बैंकिंग समस्या नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और संस्थागत संरचनाओं से जुड़ी हुई चुनौती है।

Keywords: NPA, Indian Banking, Asset Quality, Financial Stability, SARFAESI, Banking Reforms

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक वृद्धि, निवेश प्रवाह और वित्तीय स्थिरता का आधार स्तंभ है। यह प्रणाली बचत को उत्पादक निवेश में परिवर्तित करने का कार्य करती है तथा औद्योगिक, कृषि और सेवा क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) बैंकिंग क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक हैं। जब कोई ऋण 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन भुगतान में विफल रहता है, तो उसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। NPAs न केवल बैंक की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनकी ऋण देने की क्षमता को भी सीमित करते हैं।

1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, निजी और विदेशी बैंकों का प्रवेश हुआ, और ऋण वितरण में तेजी आई। हालांकि, इस विस्तार ने जोखिम प्रबंधन की चुनौतियों को भी उजागर किया।

2000 के दशक के प्रारंभ में NPAs का स्तर अत्यधिक था, जिसने बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को प्रभावित किया। हालांकि, दशक के मध्य तक इसमें गिरावट आई, जो सुधारात्मक उपायों का परिणाम थी।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) पर उपलब्ध साहित्य बैंकिंग प्रणाली की संरचना, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के व्यापक संदर्भ में विकसित हुआ है। प्रारंभिक अध्ययनों में NPAs को मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली की आंतरिक कमजोरी के रूप में देखा गया, जबकि बाद के अध्ययनों ने इसे व्यापक आर्थिक, संस्थागत और नीतिगत कारकों से जोड़कर समझने का प्रयास किया। इस प्रकार, NPAs का अध्ययन समय के साथ एक बहुआयामी (multi-dimensional) शोध क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें वित्त, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के दृष्टिकोणों का समन्वय देखने को मिलता है।

संरचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत नरसिंहम समिति (1991, 1998) की रिपोर्टें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन रिपोर्टों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में NPAs को एक गंभीर समस्या के रूप में चिह्नित करते हुए यह तर्क दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप, गैर-व्यावसायिक ऋण वितरण और कमजोर जोखिम प्रबंधन NPAs के प्रमुख कारण हैं। समिति ने prudential norms, capital adequacy और asset classification जैसे उपायों की सिफारिश की, जिन्होंने बाद में भारतीय बैंकिंग सुधारों की दिशा तय की।

संस्थागत विश्लेषण के संदर्भ में Reddy (2007) ने NPAs को केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि संस्थागत अक्षमता का परिणाम बताया। उनके अनुसार, बैंकिंग प्रणाली में जवाबदेही की कमी, कानूनी प्रक्रियाओं में देरी तथा ऋण वसूली तंत्र की कमजोरी NPAs को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि NPAs को समझने के लिए केवल वित्तीय संकेतकों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि संस्थागत ढाँचे का विश्लेषण भी आवश्यक है।

अनुभवजन्य अध्ययनों ने NPAs के निर्धारकों को सांख्यिकीय रूप से समझने का प्रयास किया है। Rajan और Dhal (2003) ने पाया कि GDP वृद्धि दर, ब्याज दर और ऋण विस्तार NPAs को प्रभावित करने वाले प्रमुख मैक्रो-आर्थिक कारक हैं। इसी प्रकार, Das और Ghosh (2007) ने बैंक-विशिष्ट कारकों—जैसे पूंजी पर्याप्तता, संचालन दक्षता और प्रबंधन गुणवत्ता—को NPAs के स्तर से संबंधित पाया। इन अध्ययनों ने NPAs को एक बहु-कारक (multi-factor) समस्या के रूप में स्थापित किया।

सार्वजनिक और निजी बैंकों के तुलनात्मक अध्ययन में Kaur (2009) ने यह निष्कर्ष निकाला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPAs का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। इसका मुख्य कारण प्रबंधन में लचीलापन की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और जोखिम मूल्यांकन में कमजोरी बताया गया। इसके विपरीत, निजी बैंकों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन प्रणाली NPAs को नियंत्रित करने में सहायक रही।

आर्थिक चक्रों के संदर्भ में Mohan (2005) ने NPAs को एक चक्रीय (cyclical) परिघटना के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, आर्थिक मंदी के दौरान उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता

कम हो जाती है, जिससे NPAs बढ़ते हैं, जबकि आर्थिक विकास के दौर में NPAs में कमी देखी जाती है। यह दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि NPAs केवल बैंकिंग प्रबंधन की समस्या नहीं हैं, बल्कि व्यापक आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं।

नीतिगत साहित्य में SARFAESI अधिनियम (2002) को NPAs नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना गया है। Mishra और Puri (2009) के अनुसार, इस अधिनियम ने बैंकों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार देकर ऋण वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया। इसके अतिरिक्त, Debt Recovery Tribunals (DRTs) और Lok Adalats जैसी संस्थाओं की स्थापना ने भी ऋण वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, हालांकि इनके कार्यान्वयन में कई व्यावहारिक सीमाएँ बनी रहीं।

अंतरराष्ट्रीय साहित्य में Berger और DeYoung (1997) ने “bad management hypothesis” प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि खराब प्रबंधन NPAs का प्रमुख कारण है। Keeton और Morris (1987) ने ऋण विस्तार और NPAs के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित किया। IMF और World Bank की रिपोर्टों ने NPAs को वित्तीय संकट के एक प्रमुख संकेतक के रूप में चिन्हित किया है, जो बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

संपूर्ण साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि NPAs पर अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों में विभाजित है—संरचनात्मक, अनुभवजन्य और नीतिगत—परंतु एक समेकित (integrated) दृष्टिकोण का अभाव है। विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में संस्थागत, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को एक साथ जोड़कर विश्लेषण करने वाले अध्ययन सीमित हैं। यही शोध-रिक्तता इस अध्ययन की आवश्यकता को स्थापित करती है, जो NPAs को एक समग्र ढाँचे में समझने का प्रयास करता है।

एक आलोचनात्मक विश्लेषण

NPAs पर उपलब्ध अधिकांश साहित्य को यदि समग्र रूप से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि शोध कार्य प्रायः दो अलग-अलग धाराओं में विकसित हुआ है—एक ओर आर्थिक

(macroeconomic/financial) कारकों पर आधारित अध्ययन, और दूसरी ओर संस्थागत (institutional/governance) कारकों पर केंद्रित विश्लेषण। हालांकि, इन दोनों दृष्टिकोणों का एकीकृत (integrated) अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित रहा है, जो NPAs की जटिल प्रकृति को समझने में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है।

प्रथम, आर्थिक कारकों पर केंद्रित अध्ययनों में NPAs को मुख्यतः व्यापक आर्थिक संकेतकों—जैसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, ऋण विस्तार और औद्योगिक उत्पादन—के संदर्भ में समझा गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, आर्थिक मंदी के दौरान उधारकर्ताओं की आय और लाभप्रदता में गिरावट आती है, जिससे ऋण अदायगी की क्षमता प्रभावित होती है और NPAs में वृद्धि होती है। इसी प्रकार, अत्यधिक ऋण विस्तार या “credit boom” भी भविष्य में NPAs के बढ़ने का कारण बन सकता है। यह दृष्टिकोण NPAs को एक प्रकार की चक्रीय (cyclical) और संरचनात्मक आर्थिक समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है।

द्वितीय, संस्थागत दृष्टिकोण NPAs को बैंकिंग प्रणाली की आंतरिक संरचनाओं, नीतिगत व्यवस्थाओं और शासन (governance) से जोड़कर देखता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक प्रबंधन की गुणवत्ता, जोखिम मूल्यांकन की दक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनी ढाँचे की प्रभावशीलता, तथा ऋण वसूली तंत्र की मजबूती जैसे कारकों को प्रमुख माना गया है। उदाहरणार्थ, कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली या गैर-पेशेवर ऋण वितरण प्रथाएँ NPAs को बढ़ावा देती हैं। इसी प्रकार, न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी या ऋण वसूली संस्थानों की अक्षमता भी समस्या को गंभीर बनाती है।

हालाँकि, इन दोनों दृष्टिकोणों की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि वे NPAs के निर्धारण में परस्पर अंतःक्रियाओं (interactions) को पर्याप्त रूप से नहीं समझते। वास्तविकता में NPAs केवल आर्थिक या केवल संस्थागत कारणों का परिणाम नहीं होते, बल्कि यह दोनों प्रकार के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आर्थिक मंदी के समय बैंकिंग प्रणाली में मजबूत जोखिम प्रबंधन और निगरानी तंत्र मौजूद हो, तो NPAs की वृद्धि को सीमित किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि संस्थागत ढाँचा कमजोर हो, तो सामान्य आर्थिक उतार-चढ़ाव भी गंभीर बैंकिंग संकट में परिवर्तित हो सकते हैं।

भारतीय संदर्भ में यह अंतर्संबंध और अधिक जटिल हो जाता है। यहाँ एक ओर विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ—जैसे असंगठित क्षेत्र की प्रमुखता, आय में असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन—NPAs को प्रभावित करती हैं; वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन संबंधी समस्याएँ, जैसे राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक हस्तक्षेप, इस समस्या को और गहरा करते हैं। उदाहरणतः, कृषि ऋण माफी योजनाएँ या प्राथमिकता क्षेत्र (priority sector) में ऋण वितरण की नीतियाँ सामाजिक दृष्टि से आवश्यक हो सकती हैं, परंतु यदि इनका उचित प्रबंधन न किया जाए, तो यह NPAs को बढ़ा सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा अनुभवजन्य अध्ययनों में भी इस संयुक्त विश्लेषण का अभाव देखा जाता है। अधिकांश शोध या तो केवल मैक्रो-आर्थिक डेटा पर आधारित होते हैं, या केवल बैंक-विशिष्ट (micro-level) संकेतकों पर। ऐसे अध्ययन अक्सर एकांगी निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो नीति-निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई अध्ययन केवल GDP वृद्धि और NPAs के बीच संबंध को दर्शाता है, तो वह यह नहीं बता पाता कि समान आर्थिक परिस्थितियों में कुछ बैंक बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं और कुछ नहीं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संयुक्त अध्ययन के अभाव में कारण और परिणाम (cause and effect) के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि NPAs आर्थिक मंदी का परिणाम हैं या स्वयं आर्थिक मंदी को बढ़ाने का कारण। इसी प्रकार, यह भी अस्पष्ट रहता है कि संस्थागत सुधारों का प्रभाव किस सीमा तक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इस संदर्भ में, एक समेकित (integrated) विश्लेषणात्मक ढाँचे की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सामने आती है, जो आर्थिक और संस्थागत दोनों कारकों को एक साथ जोड़कर NPAs की व्याख्या कर सके। ऐसा ढाँचा न केवल NPAs के वास्तविक कारणों को अधिक सटीक रूप से समझने में सहायक होगा, बल्कि यह नीति-निर्माताओं को अधिक प्रभावी और संतुलित समाधान विकसित करने में भी मदद करेगा।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि NPAs पर मौजूदा साहित्य में संस्थागत और आर्थिक कारकों के संयुक्त अध्ययन का अभाव एक महत्वपूर्ण शोध-रिक्तता (research gap) है। इस शोध का

उद्देश्य इसी रिक्तता को भरना है, जिसके अंतर्गत NPAs को एक बहुआयामी समस्या के रूप में समझते हुए विभिन्न कारकों के अंतर्संबंधों का विश्लेषण किया जाएगा। यह दृष्टिकोण न केवल सैद्धांतिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

इस अध्याय में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) से संबंधित उपलब्ध साहित्य का बहुआयामी एवं आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि NPAs पर अकादमिक विमर्श समय के साथ एक महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया से गुजरा है, जिसमें प्रारंभिक संरचनात्मक विश्लेषण से लेकर समकालीन अनुभवजन्य और नीतिगत अध्ययन तक विभिन्न दृष्टिकोण उभरे हैं।

प्रारंभिक साहित्य में NPAs को मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली की आंतरिक कमजोरियों—जैसे खराब ऋण मूल्यांकन, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप—के परिणाम के रूप में देखा गया। इस चरण में ध्यान संस्थागत सुधारों, विशेषकर बैंकिंग विनियमन, पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानकों के विकास पर केंद्रित रहा। इसके पश्चात, अनुभवजन्य अध्ययनों ने NPAs के निर्धारकों को सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास किया, जिसमें मैक्रो-आर्थिक संकेतकों (जैसे GDP वृद्धि, ब्याज दर) और बैंक-विशिष्ट कारकों (जैसे प्रबंधन दक्षता, पूंजी संरचना) के प्रभावों को रेखांकित किया गया।

हालांकि, नीतिगत साहित्य ने NPAs की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों—जैसे SARFAESI अधिनियम, Debt Recovery Tribunals, तथा RBI के prudential norms—का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया कि संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ बनाकर इस समस्या को आंशिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बावजूद, इन उपायों की प्रभावशीलता पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही, क्योंकि व्यावहारिक कार्यान्वयन में कई बाधाएँ विद्यमान रहीं।

इस साहित्य समीक्षा का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि NPAs को समझने के लिए उपलब्ध अध्ययन प्रायः खंडित (fragmented) दृष्टिकोण अपनाते हैं। एक ओर आर्थिक कारकों पर केंद्रित

अध्ययन NPAs को चक्रीय और संरचनात्मक आर्थिक समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर संस्थागत दृष्टिकोण इसे शासन, प्रबंधन और नीतिगत कमजोरियों से जोड़ता है। परंतु इन दोनों आयामों के बीच अंतर्संबंधों का समेकित विश्लेषण अपेक्षाकृत सीमित है।

विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में यह कमी और अधिक स्पष्ट रूप से उभरती है, जहाँ NPAs की प्रकृति सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संरचना, तथा नीतिगत प्राथमिकताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। उपलब्ध साहित्य यह संकेत देता है कि केवल आर्थिक सुधार या केवल संस्थागत सुधार NPAs की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक समग्र (holistic) दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो दोनों प्रकार के कारकों को एक साथ समाहित करे।

इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट होता है कि NPAs पर अधिकांश अध्ययन अल्पकालिक प्रवृत्तियों या विशिष्ट कारकों तक सीमित हैं, जबकि दीर्घकालिक (longitudinal) और तुलनात्मक (comparative) विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, कई अध्ययन सांख्यिकीय विश्लेषण तक सीमित रहते हैं और वे नीति-निर्माण के लिए आवश्यक व्याख्यात्मक (interpretive) अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं कर पाते।

इस प्रकार, यह अध्याय यह स्थापित करता है कि NPAs की समस्या को समझने के लिए एक समेकित विश्लेषणात्मक ढाँचे की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक, संस्थागत और नीतिगत कारकों के अंतर्संबंधों का गहन अध्ययन किया जा सके। यही शोध-रिक्तता इस अध्ययन की बौद्धिक आवश्यकता को परिभाषित करती है।

अंततः, यह साहित्य समीक्षा आगे के अध्यायों के लिए एक सुदृढ़ सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करती है। विशेष रूप से, आगामी अध्याय में प्रस्तुत सैद्धांतिक रूपरेखा (Theoretical Framework) इसी आधार पर विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से NPAs को एक बहुआयामी समस्या के रूप में समझने का प्रयास किया जाएगा।

संदर्भ सूची

1. Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*.

2. Narasimham Committee Report (1998). *Banking Sector Reforms*.
3. Reddy, Y. V. (2007). *Financial Sector Reforms in India*.
4. Rajan, R., & Dhal, S. (2003). "Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India." RBI Occasional Papers.
5. Das, A., & Ghosh, S. (2007). "Determinants of Credit Risk in Indian State-Owned Banks."
6. Kaur, J. (2002). "Performance of Public and Private Sector Banks."
7. Mohan, R. (2005). *Financial Sector Reforms in India: Policies and Performance Analysis*.
8. Mishra, B. S., & Puri, V. K. (2010). *Indian Economy*.
9. Reserve Bank of India (2009). *Report on Trend and Progress of Banking in India*.
10. Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks."
11. Keeton, W. R., & Morris, C. S. (1987). "Why Do Banks' Loan Losses Differ?"
12. IMF (2005). *Global Financial Stability Report*.
13. RBI (1995–2010). *Various Annual Reports*.



EARN YOUR MBA

WWW.IIMPS.IN



Accreditation & Ranking



UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

☎ 011-41005174

R
S
E
A
R
C
H
G
A
T
E
W
A
Y

STOP PLAGIARISM



Arogyam Ayurveda
Holistic Healing through herbs



A
R
O
G
Y
A
M
O
N
L
I
N
E

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER



COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD



- BLUE** Calms your Child's Mind & Body
- YELLOW** Promotes Concentration, Stimulates the Memory
- PINK** Evokes Empathy, makes your Child Calm
- RED** Excites and energizes your Child's body
- GREEN** Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com



भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY**

ISSN – 2250 – 1959 (O) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
COMMERCE, ARTS AND SCIENCE**

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES**

ISSN 2277 – 9809 (O) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSSH.COM



**INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE
ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM



**INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF
MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION**

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMISI.COM



**JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS
AND ECONOMICS RESEARCH**

WWW.JLPER.COM

JLPE